

राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत लगाये पाबंदी आदेश
वैध पहचान पत्र के बिना मोबाईल कनेक्शन नहीं दिये जाएं

जयपुर, 10 जनवरी। विभिन्न सैल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स व सब रिटेलर्स और दुकानदारों को बिना ग्राहक की वैध पहचान और पते का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये बिना सिम कार्ड, सैल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन नहीं दिये जाएं।

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व, श्री हनुमान प्रसाद द्वारा जयपुर पूर्व क्षेत्र में लोक-शांति एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों में यह कहा गया है कि विभिन्न सैल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स एवं सब-रिटेलर्स द्वारा दूसरों के नाम से व छद्म नाम के कूटरचित पहचान-पत्रों के आधार पर भी बिना भौतिक सत्यापन के मोबाईल कनेक्शन व सिम कार्ड जारी किये जा रहे हैं। इन कंपनियों से समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी व आतंकवादी तत्वों द्वारा अपने आपराधिक मंसूबों की पूर्ति हेतु कनेक्शन व सिम कार्ड प्राप्त कर इनका प्रयोग अवाञ्छित कार्यों व अपराधों में करने की आसूचनाये भी प्राप्त हुई है। कूटरचित पहचान-पत्रों के आधार पर दूसरों के नाम से व छद्म नाम जारी सैल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन व सिम का प्रयोग आतंकवादी वारदातों को अजांम देने में भी किये जाने की पूर्ण संभावना है।

इसे देखते हुए ही धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत विभिन्न सैल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स एवं सब-रिटेलर्स एवं ऐसे दूसरे सभी दुकानदारों को पाबन्द किया गया है कि ग्राहक को वैध पहचान तथा पते का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये बिना कोई सैल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन व सिम कार्ड जारी नहीं करेंगे। रिटेलर्स, सब रिटेलर्स एवं ऐसे दुकानदार द्वारा बेची गई सिम कार्ड की कंपनी का नाम आई.डी. नम्बर सहित सिम कार्ड के क्रेता का पूर्ण विवरण नाम पिता का नाम पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता बेसिक फोन नम्बर पूर्व में प्रयोग किये जा रहे सैल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन नम्बर तथा सिम जारी करने के लिये प्राप्त दस्तावेजों की पूर्ण सूचना रखेंगे। समस्त सैल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कंपनियां अपना सैल्यूलर मोबाईल फार्म नम्बर व सिम जारी करने का रिकार्ड हमेशा के लिये तथा रिटेलर्स व सब रिटेलर्स एवं दुकानदार प्रीपेड/ पोस्टपेड मोबाईल कनेक्शन की बिक्री की दैनिक सूचना रजिस्टर में संधारित कर 05 साल तक उक्त रिकार्ड को सुरक्षित रखेंगे तथा जॉच एजेन्सियों द्वारा मांगने पर उक्त रिकार्ड को अविलम्ब उपलब्ध करवायेगे।

आदेशों में विदेशी नागरिकों को सिम कार्ड केवल उसके पासपोर्ट व वीजा की आई.डी. पर ही देने तथा वह विदेशी नागरिक जिस होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला इत्यादि में रुका हुआ है उसकी भी आई.डी. पुफ लेने के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 9 मार्च 2018 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।

राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

पुलिस सत्यापन के बिना घरेलू नौकर, चौकीदार, ड्राइवर आदि न रखे जाएं

जयपुर, 10 जनवरी। बिना पुलिस सत्यापन करवाये व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि नहीं रखे जाएं।

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व, श्री हनुमान प्रसाद द्वारा जयपुर पूर्व क्षेत्र में लोक-शांति एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के तहत ऐसे व्यक्ति व संस्थायें जो घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि रखते हैं, उन्हें पुलिस सत्यापन करवाये बिना व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि नहीं रखने के निर्देश दिये गये हैं।

आदेश के अनुसार मकान मालिक, संस्थाओं, दुकानदारों को घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन आदि रखे जाने पर उनका फोटो सहित पूर्ण विवरण— नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, पहचान चिन्ह (हुलिया), पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता, भाषा, बेसिक फोन नम्बर/सेल्यूलर मोबाइल फोन नम्बर, परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थानीय पहचान कर्ता व मूल निवास का पहचान कर्ता का टेलिफोन/मोबाइल न0 सहित नाम व पता का विवरण अपने पास रखना होगा। इसके साथ ही नौकर, चौकीदार, सैल्समेन के स्थानीय जमानती/रिश्तेदार/जानकार का टेलिफोन/मोबाइल न0 सहित नाम व पता का विवरण, पिछले पाँच सालों में जहाँ निवास व नौकरी की गई वहाँ के मालिक का नाम व पता, अदालत में चल रहे आपराधिक प्रकरणों का विवरण, वैध एवं प्रमाणिक पहचान-पत्र की प्रतियाँ इत्यादि की पूर्ण सूचना सुरक्षित रखनी होगी तथा इनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करना होगा। आदेश में इन सूचनाओं के साथ ही इनकी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना भी तत्काल संबंधित पुलिस थानें में देनी होगी।

इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 9 मार्च 2018 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।

राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

पुलिस सत्यापन के बिना निजी छात्रावास में छात्र न रखे जाएं

जयपुर, 10 जनवरी। बिना पुलिस सत्यापन करवाये व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना शहर के किसी भी निजी छात्रावास में छात्र नहीं रखे जाएं।

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व, श्री हनुमान प्रसाद द्वारा जयपुर पूर्व क्षेत्र में लोक-शांति एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के तहत ऐसे व्यक्ति व संस्थायें जो निजी छात्रावासों में छात्र रखते हैं, को पाबन्द किया जाता है कि निजी छात्रावासों में ऐसे किसी छात्र का किरायेदार की हैसियत से उनका पूर्ण प्रमाणिक व्यक्तिगत विवरण व पुलिस सत्यापन करवाये बिना नहीं रखेंगे। छात्र का फोटो सहित पूर्ण विवरण यथा नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, हुलिया, वर्तमान व स्थाई पूर्ण पता, भाषा, बेसिक टेलीफोन नम्बर/ सेल्यूलर मोबाईल फोन नम्बर, परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थाई पहचानकर्ता व मूल निवास का पहचानकर्ता के बेसिक टेलीफोन नम्बर, मोबाईल फोन नम्बर सहित पूर्ण नाम व पता, अदालत में चल रहे आपराधिक प्रकरणों का विवरण, वैध एवं प्रमाणिक पहचान पत्र की प्रतियां इत्यादि की पूर्ण सूचना सुरक्षित रखेंगे तथा इनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करेंगे। उपर्युक्त सूचनाओं के साथ ही इनकी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल संबंधित पुलिस थाने में देनी होगी।

इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 9 मार्च 2018 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।

राजस्थान सरकार
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

लिखित अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन नहीं किया जाए

जयपुर, 10 जनवरी। लिखित अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संगठन को धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा का आयोजन नहीं किये जाने के निर्देश दिये हैं।

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व, श्री हनुमान प्रसाद द्वारा जयपुर पूर्व क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि जयपुर महानगर में विभिन्न राजनैतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं तथा किसान, मजदूर, छात्र, युवा, व्यापारी संगठनों आदि के द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा इत्यादि का आयोजन किया जाता है। जिसमें भारी संख्या में जनसमुदाय की सहभागिता रहती है। ऐसे आयोजनों में कई बार जिला प्रशासन को केवल सूचना प्रदान की जाती है और अनेक अवसरों पर बिना अनुमति या सूचना के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लिए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से नगरीय जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है तथा विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं, रोगियों तथा जन साधारण को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बिना सूचना एवं अनुमति के आयोजन करने की स्थिति में मौके पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाना भी कठिन होता है। जिसकी वजह से किसी अवांछनीय घटना के घटित होने की संभावना बनी रहती है।

इसे देखते हुए ही दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) के क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त पूर्व/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्व) की लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संगठन धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा का आयोजन नहीं करेंगे एवं इस हेतु उन्हें आयोजन की तिथि से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। यह प्रतिबंध विवाह समारोह, मृत्यु संबंधी संस्कारों, परम्परागत धार्मिक या सांस्कृतिक शोभायात्राओं, विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों से संबंधित राजकीय समारोह एवं शिक्षा साक्षरता, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि से संबंधित राजकीय आयोजनों पर लागू नहीं होगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 9 जनवरी 2018 को प्रातः 10 बजे से 9 मार्च 2018 की मध्यरात्रि तक तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावी रहेगा।